(घ) अधिकांश राज्यों में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए अनुरोध किया है और गुजरात तथा मध्य प्रदेश समेत विद्युत उत्पादन परियोजनाएं अधिष्ठापित की जा रही हैं। इन राज्यों के नाम निम्नवत हैं :—

1. आन्ध्र प्रदेश
2. अरुणाचल प्रदेश
3. असम
4. बिहार
5. दिल्ली
6. गुजरात
7. हरियाणा
8. हिमाचल प्रदेश
9. केरल
10. कर्नाटक
11. महाराष्ट्र
12. मध्य प्रदेश
13. उड़ीसा
14. राजस्थान
15. तमिलनाडु
16. उत्तर प्रदेश
17. पश्चिम बंगाल

गुजरात में 2565 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता वाली 5 विद्युत परियोजनाएं पहले ही निजी क्षेत्र को सौंपी जा चुकी हैं। उनका कुछेक अन्य परियोजनाओं को भी बोली के माध्यम से निजी क्षेत्र को सौंपे जाने का प्रस्ताव है।

मध्य प्रदेश में 56.52 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता हेतु 12 विद्युत परियोजनाएं निजी क्षेत्र को सौंपी गई है और राज्य सरकार द्वारा बोली के माध्यम से कुछ अन्य परियोजनाएं सौंपे जाने की भी प्रत्याशा है।

(ङ) गांधार में गैस-आधारित विद्युत संयंत्र अधिष्ठापित किया गया है, जिसमें 131— मेगावाट के 3 गैस टर्बाइन शामिल हैं। इस केन्द्र के स्टीम टर्बाइन यूनिट को मार्च, 1995 में चालू किए जाने की आशा है। इसके अलावा, दो परियोजनाएं यथा गांधार (पागुथन) सीसी-जीटी-655 मेगावाट और बड़ौदा जिले में गुजरात इण्डस्ट्रियल पावर कम्पनी लि. 145 मेगावाट के विद्युत संयंत्र हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

Inadequate coal supply

310. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether power generation has been decreasing in the country particularly in Uttar Pradesh due to inadequate supply of coal during the last three years;

(b) if so, the reasons for the reduction in coal supply; and

(c) the measures taken by Government to remove shortage in the supply of coal?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL): (a) No, Sir.

(b) The question does not arise.

(c) The position of coal supply to all the thermal power stations in the country including those in Uttar Pradesh, is kept under constant review including at the high level interdepartmental weekly meetings, and the remedial actions are taken from time to time.

कहलगांव ताप विद्युत परियोजना में विद्युत उत्पादन

311. **श्री जनार्दन यादव** : क्या विद्युत मंत्री 13 दिसम्बर, 1994 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न सं. 1048 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कहलगांव ताप विद्युत परियोजना में इस समय कितनी मात्रा में बिजली का उत्पादन किया जा रहा है,

(ख) इस परियोजना द्वारा स्थानीय स्तर पर कितनी मात्रा में बिजली की आपूर्ति की जा रही है; और

(ग) स्थानीय विकास के प्रयोजनार्थ इस परियोजना द्वारा कितनी धनराशि दी जा रही है, ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल): (क) चालू वर्ष (अप्रैल, 1994 फरवरी, 1995) के दौरान कहलगांव ताप विद्युत परियोजना से 439 मि.यू. विद्युत का उत्पादन किया गया था ।

(ख) इस परियोजना से उत्पादित विद्युत ग्रिड को प्रदान की जाती है तथा बिहार राज्य बिजली बोर्ड द्वारा स्थानीय वितरण किया जाता है ।

(ग) कहलगांव सुपर ताप विद्युत परियोजना द्वारा स्थानीय विकास हेतु अभी तक 211.83 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं ।

Delay in Dulhasti Power Project

312. DR. NAUNIHAL SINGH: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Dumex Segee Borie (DSB), the French Company responsible for civil construction of the Dulhasti Power Project has pulled out of the consortium led by Cagelac; if so, what are the reasons thereof;

(b) what steps Government have taken to fill this gap;

(c) whether it is a fact that the cost of the over-all project will go higher than estimated earlier due to this delay caused by the changed situation; and

(d) what steps Government have taken to meet such a situation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL): (a) The French Company, M/s. Dumez-Sogea-Borie (DSB), was not prepared to continue work at the project site in view of its perception of the security environment prevailing in the area. With a view to resuming work on the project, an Understanding was reached between NHPC and the Fernch Consortium on 29.6.1994 envisaging termination of the contract with DSB and continuation of the remaining four members of the Consortium with their obligations.

(b) The Government has allowed NHPC to get the balance civil works completed by making alternative arrangements.

(c) The cost of the over-all project would go up on account of various factors, including exchange rate variation, settlement with the French Consortium and delay in commissioning.

(d) The steps taken to meet the situation include strengthening of security arrangements in and around the project area and facilitating take-over of the works and construction equipment/machinery from DSB by NHPC with a view to resuming work on the project by making alternative arrangements for completion of the balance civil works.

Agreement with USA on power projects

313. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA:

SHRI BHAGABAN MAJHI:

Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether Government have signed agreements with US on power projects recently;